

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2024—चैत्र 23, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक ई 1-06/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2023 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति उपरांत राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ करता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थल
(1)	(2)	(3)
1.	सुश्री अनुपमा आनंद	रायपुर

(1)	(2)	(3)
2.	श्री एम भार्गव	दुर्ग
3.	श्री तन्मय खन्ना	बिलासपुर
4.	श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी	जांजगीर-चांपा

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2024

क्रमांक एफ 5-1/2024/एक (1).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 से 19 दिसम्बर, 2023 तक कुल (09 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश तथा अवकाश पूर्व दिनांक 09-12-2023 से 10-12-2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मार्च 2024

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 15-01-2024 से 19-01-2024 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 13-01-2024 से 14-01-2024 तक तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 20-01-2024 से 21-01-2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मार्च 2024

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 05-02-2024 से 09-02-2024 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 03-02-2024 से 04-02-2024 तक तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 10-02-2024 से 11-02-2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक/1241/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र./5923/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2,

दिनांक 30-11-2021, क्र./1578/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, दिनांक 23-03-2022, क्र./4176/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2, दिनांक 01-07-2022, क्र./5286/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, दिनांक 29-08-2022 तथा क्र./83/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2, दिनांक 10-01-2023 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो तथा विनिर्माण में उपयोग में लाये जाने के पश्चात् उपज के प्रसंस्करण/विनिर्माण के विक्रय किये जाने पर कीमत के प्रत्येक 100 रु. पर, 1.5 रु. की दर से मंडी शुल्क और 0.5 रु. की दर से कृषक कल्याण शुल्क तथा शेष अधिसूचित कृषि उपजों (धान को छोड़कर), पर 1 रु. की दर से मंडी शुल्क और 0.5 रु. की दर से कृषक कल्याण शुल्क नियत करती है।

यह दरें आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, विशेष सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक/1241/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1241/रायपुर दिनांक 13-03-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, विशेष सचिव.

Nava Raipur, the 13th March 2024

No./1241/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), and supersession in this Department's Notification No./5923/D-15/116/Part-2/2004/14-2, dated 30-11-2021, No./1578/D-15/116/Part-2/2004/14-2, dated 23-03-2022, No./4176/D-15/116/Part-3/2004/14-2, dated 01-07-2022, No./5286/D-15/116/Part-2/2004/14-2, dated 29-08-2022, and No./83/D-15/116/Part-3/2004/14-2, dated 10-01-2023, the State Government, hereby, fixes the market fees at the rate of Rs. 1.5 and Farmer Welfare fee at the rate of Rs. 0.5 on the value of per Rs. 100 on the sale of notified agricultural produce, whether brought to a market area from within the state or from outside the State and on the sale of processed/manufactured product after being put to use in manufacturing and on remaining notified agricultural produce (except paddy), Market fee at the rate of Rs. 1 and farmer welfare fee at the rate of Rs. 0.5.

These rates shall be effective till next order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SARANSH MITTAR, Special Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मार्च 2024

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक ECI/PN/23/2024, दिनांक 16-03-2024 के अनुसार राज्य में निम्नानुसार मतदान नियत है :—

क्र.	मतदान की तिथि	संसदीय क्षेत्र क्रमांक	संसदीय क्षेत्र का नाम
1.	19-04-2024	10	बस्तर
2.	26-04-2024	6, 9, 11	राजनांदगांव, महासमुन्द, कांकेर
3.	07-05-2024	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 646/782/2024/1-5, दिनांक 21-03-2024 में लोकसभा निर्वाचन-2024 के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र क्रमांक 439/स्था/लो.स.नि./2024/2072, दिनांक 16-03-2024 के साथ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक ECI/PN/23/2024, दिनांक 16-03-2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख, “मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी” में उल्लेखित प्रावधान अनुसार लोकसभा निर्वाचन, 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् प्रथम चरण में दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) द्वितीय चरण में दिनांक 26 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) एवं तृतीय चरण में दिनांक 07 मई, 2024 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित करता है।

3. साथ ही कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र क्रमांक 439/स्था/लो.स.नि./2024/2689, दिनांक 27-03-2024 के अनुसार आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं तेलंगाना राज्य के लोकसभा निर्वाचन-2024, हेतु निम्नानुसार मतदान तिथि का निर्धारण किया गया है :—

क्र.	राज्य का नाम	मतदान तिथि						
1	2	3						
1	आंध्रप्रदेश,	13.05.2024						
2	उड़ीसा,	13.05.2024	20.05.2024	25.05.2024	01.06.2024			
3	महाराष्ट्र	19.04.2024	26.04.2024	07.05.2024	13.05.2024	20.05.2024		
4	मध्यप्रदेश,	19.04.2024	26.04.2024	07.05.2024	13.05.2024			
5	उत्तरप्रदेश,	19.04.2024	26.04.2024	07.05.2024	13.05.2024	20.05.2024	25.05.2024	01.06.2024
6	झारखंड,	13.05.2024	20.05.2024	25.05.2024	01.06.2024			
7	तेलंगाना	13.05.2024						

4. उपरोक्तानुसार क्रमशः नियत मतदान तिथि को, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है।

5. साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 9 मार्च 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11)

क्रमांक/789/202403200400013/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है.

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
कोण्डागांव	केशकाल	उमरादाह	26	0.8835 हे.	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-03-2024 को समय 11.00 बजे स्थान स्कूल प्रांगण-उमरादाह पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण.
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या—	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	0.8835 हे.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	—	2281.26 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित निर्माण पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोण्डागांव, दिनांक 9 मार्च 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11)

क्रमांक/790/202403200400014/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
कोण्डागांव	केशकाल	सेन्दूरमेटा	13	0.7726 हे.	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-03-2024 को समय 11.00 बजे स्थान स्कूल प्रांगण-उमरादाह पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण.
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	13
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या—	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	0.7726 हे.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	—	2281.26 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित निर्माण पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/08/अ-82/2022-23.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	रतखण्डी	2.61 एकड़ 1.054 हेक्टेयर	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत बरर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 11-06-2024 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम रतखण्डी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत बरर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत बरर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	5077.74 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/17/अ-82/2022-23.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	लूफा	16.26 एकड़ 7.100 हेक्टेयर	लूफा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 07-06-2024 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम लूफा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लूफा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	लूफा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	917.81 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/18/अ-82/2022-23.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	उपका	0.19 एकड़ 0.076 हेक्टेयर	उपका व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 06-06-2024 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम उपका पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उपका जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	उपका व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	130.64 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/44/अ-82/2017-18.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	अमाली	0.80 एकड़ 0.323 हेक्टेयर	सलका व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण पूरक प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 10-06-2024 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम अमाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सलका व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण पूरक प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	सलका व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण पूरक प्रकरण
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1880.00 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	—
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 18 मार्च 2024

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2022-23/425.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	झिंगटपुर प.ह.नं. 21	3.297	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नवागांव व्यपवर्तन योजना मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800004/अ-82/2022.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा ग्राम-राजपुर, प.ह.नं.-03, रा.नि.म.-राजपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.), की निजी भूमि कुल रकबा 0.024 हे. धरमजयगढ़-कापू मार्ग के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 एवं धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 09-12-22 को एवं दिनांक 24-03-23 को क्रमशः कराया गया है.

चूंकि अब परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-अर्जन कार्यवाही में खसरा क्र. 222/1 का रकबा 0.060 हे., 14/2 का रकबा 0.010 हे., 366/5 का रकबा 0.014 हे., क्रमशः प्रकाशित हुआ है, परंतु वास्तव में मौका जांच उपरांत 0.084 हे. को भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-राजपुर		
क्र.	खसरा नं.	रकबा
01	222/1	0.060
02	14/2	0.010
03	366/5	0.014
कुल खसरा-03		कुल रकबा-0.084 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800014/अ-82/2022.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा ग्राम-सराईमुड़ा, प.ह.न.-02, रा.नि.म.-राजपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की निजी भूमि कुल रकबा 0.088 हे. धरमजयगढ़-कापू मार्ग के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 एवं धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 09-12-22 को एवं दिनांक 24-03-23 को क्रमशः कराया गया है.

चूंकि अब परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा भू-अर्जन कार्यवाही में खसरा क्र. 35/5 का रकबा 0.008 हे., 49/2 का रकबा 0.006 हे., 53/14 का रकबा 0.004 हे. एवं 53/10 का रकबा 0.003 हे. 139/3 का रकबा 0.003 हे., 139/4 का रकबा 0.002 हे., 218/12 का रकबा 0.032 हे., 175/1 का रकबा 0.030 हे., क्रमशः प्रकाशित हुआ है, परंतु वास्तव में मौका जांच उपरांत 0.088 हे. को भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-सराईमुड़ा		
क्र.	खसरा नं.	रकबा
01	35/5	0.008
02	49/2	0.006
03	53/14	0.004
04	53/10	0.003
05	139/3	0.003
06	139/4	0.002
07	218/12	0.032
08	175/1	0.030
कुल खसरा-08		कुल रकबा-0.088 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 फरवरी 2024

क्रमांक 19/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बेलगहना
(ग) नगर/ग्राम-खोंगसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/10	0.255
8/1/3	0.255
10	0.121
योग	3
	0.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमाडबरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2024

प्रकरण क्रमांक 1081/01/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-रतनपुर
(ग) नगर/ग्राम-जोगीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.675 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/1	0.069
128/1	0.049
128/2	0.049
139/2	0.040
129/1	0.028
129/2	0.028
129/3	0.028
129/5	0.028
130	0.016
138/1	0.065
139/1	0.113
139/8	0.101
139/6ख	0.061
योग	13
	0.675

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मंगला-भैसाझार मार्ग लम्बाई 25.958 कि.मी. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्रमांक/1234/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		140/3ग, 143/11	0.037
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही		140/3ख, 143/10	0.037
(ख) तहसील-पेण्ड्रा रोड		141/8	0.081
(ग) नगर/ग्राम-टीकरकला			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.322 हेक्टेयर	योग	09	0.322
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण कार्य गौरेला बायपास मार्ग हेतु.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	
159/7	0.065	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लीना कमलेश मंडावी , कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
159/11	0.065		
140/3घ, 143/12	0.037		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन,
सेक्टर-24, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6088.— कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2141-2142 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री दशमत जंघेल	अध्यक्ष
2.	श्री महेश साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रकाश जैन	सदस्य
4.	श्री जैतराम कोसरे	सदस्य
5.	श्री रामअवतार नेताम	सदस्य
6.	श्री गिरधारी पाल	सदस्य
7.	श्रीमती तरूण साहू	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री सी. पी. नायक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6090.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2105-2106 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गण्डई, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री संजू चंदेल	अध्यक्ष
2.	श्रीमती जानकी मरावी	उपाध्यक्ष
3.	श्री किशुन मिरचे	सदस्य
4.	श्री फारूख मेमन (व्यापारी)	सदस्य
5.	श्री शत्रुघन चंदेल	सदस्य
6.	श्रीमती प्रियंका जंधेल	सदस्य
7.	श्री रामानंद साहू	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री सी. के. उइके, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गण्डई, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6092.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2137-2138 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री नीलकंठ साहू	अध्यक्ष
2.	श्री चोवा साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री भागवत पटेल	सदस्य
4.	श्रीमती रानू दुबे	सदस्य
5.	श्री संजय लिखाटे	सदस्य
6.	श्री आनंद ओग्रे	सदस्य
7.	श्री रामफल कौशिक (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6094.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2139-2140 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री डोमन मरकाम	अध्यक्ष
2.	श्री सुभाषपुरी गोस्वामी	उपाध्यक्ष
3.	श्री साधेलाल अनंत	सदस्य

4.	श्री सीताराम पटेल	सदस्य
5.	श्री सुंदर साहू	सदस्य
6.	श्री योगेन्द्र ठाकुर	सदस्य
7.	श्री मोहन देवांगन (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री सुरेश चंद्र प्रसाद, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6096.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2147-2148 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री गरीबा यादव	अध्यक्ष
2.	श्री प्रेम भास्कर	उपाध्यक्ष
3.	श्री गोविंद साहू	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र ध्रुव	सदस्य
5.	श्रीमती सतीबाई कश्यप	सदस्य
6.	श्री देव प्रसाद डडसेना	सदस्य
7.	श्री दिलेश्वर सिंगरोल (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री ए. के. सत्यपाल, वरि. कृषि विकास अधिकारी, संभागीय कार्यालय बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6098.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2187-2188 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री संदीप शुक्ला	अध्यक्ष
2.	श्री अश्वनी उद्देश	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती आशा	सदस्य
4.	श्री कुलवंत सिंह	सदस्य
5.	श्री शिवदयाल निर्मलकर	सदस्य
6.	श्री मोती पैकरा	सदस्य
7.	श्री सुभाष अग्रवाल (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री आर. ए. साहू, वरि. कृषि विकास अधिकारी, संभागीय कार्यालय बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोटा, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6100.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2189-2190 रायपुर दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी —

1.	श्री शंकर यादव	अध्यक्ष
2.	श्री संतोष दुबे	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रमोद जायसवाल	सदस्य
4.	श्री रामेश्वर साहू	सदस्य
5.	श्री मेघनाथ खांडेकर	सदस्य
6.	श्रीमती कामिनी दिनकर	सदस्य
7.	श्री देवसिंह पोर्ते	सदस्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री आर. पी. गुप्ता, वरि. कृषि विकास अधिकारी, संभागीय कार्यालय बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भारसाधक समिति/32(2)/2023-24/6228.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/भारसाधक समिति/32(2)/2023-24/6140 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला-बलरामपुर में श्री हरिराम एक्का वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शंकरगढ़ जिला बलरामपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला-बलरामपुर में श्री हरिराम एक्का वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शंकरगढ़ के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार भगत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुसमी को कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भारसाधक अधिकारी/32(2)/2023-24/6296.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/भारसाधक समिति/32(2)/2023-24/6134 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला-सक्ती में श्री नारायण प्रसाद गभेल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला-सक्ती को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला-सक्ती में श्री नारायण प्रसाद गभेल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला सक्ती के स्थान पर श्री वतन जाधव कृषि विस्तार अधिकारी मालखरौदा को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला सक्ती का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

यशवंत कुमार,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th February 2024

No. 3769/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate Second Class	Present place of posting	Present Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Ankita Yadu, J.M.S.C., Raipur,		
2.	Ku. Preeti Jha, J.M.S.C., Raipur,		
3.	Shri Harshwardhan Jaiswal, J.M.S.C., Raipur,	Raipur	Raipur
4.	Ku. Soumya Rai, J.M.S.C., Raipur,		
5.	Ku. Akansha Khalkho, J.M.S.C., Raipur		

Bilaspur, the 29th February 2024

No. 3771/Checker/III-6-2/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Divya Goyal, J.M.F.C., Sakti,	Sakti	Janjgir-Champa
2.	Shri Vikas Khandey, J.M.F.C., Janjgir.	Janjgir	

बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2024

क्रमांक 105/दो-3-18/2007.—श्री डाक्टरलाल कटकवार, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा (छ.ग.) दिनांक 31-01-2023 की अपराह्न में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 250 (दो सौ पचास) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24, दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है।

By order of the High Court,
SUDHIR KUMAR, Registrar General.